भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1857
दिनांक 11 दिसंबर 2025

प्राकृतिक गैस अवसंरचना का विस्तार

1857. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

श्री विनोद लखमशी चावड़ाः

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

श्री मनोज तिवारीः

श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

श्री अभिमन्यु सेठीः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

डॉ. भोला सिंहः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

श्री राजकुमार चाहरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड, विशेषकर मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर जिलों में, के कार्य को पूरा करने और अंतर-संपर्क में तेजी लाने की किस प्रकार की योजना है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सहित अल्पसेवित गैस आपूर्ति वाले जिलों में गैस आपूर्ति में सुधार करने के लिए किसी नए मार्ग या स्पर-लाइन की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय गैस एक्सचेंज में तरलता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और सरकार किस प्रकार छोटे बाजार के हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है;

(घ) वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बीच, अनुमानित पंद्रह प्रतिशत गैस भागीदारी की मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी अनुबंध प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र के पालघर जिले में राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन ग्रिड के अंतर-संपर्क में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों (एनजीपीएल) को बिछाने, विनिर्माण, प्रचालन और विस्तार हेतु कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। देश भर में (अयोग्य क्षेत्रों सहित) प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबी ने विभिन्न कंपनियों को, देश भर में लगभग 34,233 किलोमीटर लंबे एनजीपीएल नेटवर्क, जिसमें कॉमन कैरियर, स्पर लाइन, टाई-इन कनेक्टिविटी और समर्पित पाइपलाइन शामिल हैं, को प्राधिकृत किया है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से, सरकार लगातार संबंधित राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा और समन्वय करती है ताकि भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार (आरओयू) हासिल करना, वन और पर्यावरण अनुमति प्राप्त करना, नदियों, नहरों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे क्रॉसिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त करना, जिसमें कई प्राधिकरण शामिल हैं, आदि जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर (एचवीजे) पाइपलाइन प्रणाली (राष्ट्रीय गैस ग्रिड का भाग) का लगभग 10 कि.मी. का स्पर-लाइन नेटवर्क जो देवास, पीथमपुर और इंदौर और उसके आसपास कनेक्टिविटी देता है, प्रचालन में है। शाजापुर जिले में, एचवीजे पाइपलाइन, दाहेज-विजयपुर पाइपलाइन-I और दाहेज-विजयपुर पाइपलाइन-II (राष्ट्रीय गैस ग्रिड का भाग) का भाग बनने वाली लगभग 57 कि.मी. की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालन में है।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, एचवीजे पाइपलाइन प्रणाली (राष्ट्रीय गैस ग्रिड का भाग) का लगभग 89 कि.मी. का स्पर-लाइन नेटवर्क चालू है, जो बुलंदशहर और उसके आसपास कनेक्टिविटी देता है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में, दाहेज-उरण पाइपलाइन नेटवर्क और दाभोल-पनवेल पाइपलाइन नेटवर्क (डीयूपीएल-डीपीपीएल) (राष्ट्रीय गैस ग्रिड का भाग) का लगभग 127 कि.मी. का स्पर-लाइन नेटवर्क चालू है।

सरकार ने उन घरेलू गैस उत्पादकों को, जिन्हें मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता दी गई है, को पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत गैस विनिमय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 500 एमएमएससीएम या उनके संविदागत क्षेत्रो से वार्षिक उत्पादन का 10%, जो भी अधिक हो, घरेलू गैस बेचने की अनुमति दी है।

पीएनजीआरबी ने बताया है कि उसने इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) पर तरलता, पारदर्शिता और व्यापार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आईजीएक्स को छह क्षेत्रीय गैस हब और अधिक भागीदारों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त डिलीवरी बिंदुओं को प्रचालित करने की अनुमति देना; विनिमय पर अधिकतम-मूल्य घरेलू गैस और स्मॉल-स्केल एलएनजी (एसएसएलएनजी) सेगमेंट्स शुरू करना; और मार्केट डेप्थ और प्राइस डिस्कवरी को बेहतर बनाने के लिए 3 और 6 माह की लंबी अवधि के संविदाओं के साथ-साथ माह- के- शेष संविदाओं की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा, छोटे उत्पादकों की बाजार में आसान पहुंच बनाने के लिए, विनिमय 50 एमएमबीटीयू/प्रति दिन (1250 एससीएमडी) के छोटे आकार में व्यापार की सुविधा देता है।

सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) श्रेणी में रखा है, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं के साथ आपसी सहमति से तय व्यवसायिक शर्तों पर अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से लंबे समय के एलएनजी संविदाओं को प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी।

*****